उत्तर्ज और सिंचाई तथा कोवला मंत्री (भी ए. बी. ए. गनी सान चौधरी) : जी नहीं । सरकारी बिजली घरों के निर्माण का कार्य निजी क्षेत्र को दिए जाने का कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं है । बिजली घरों के वास्तविक निर्माण के बारे में वर्तमान प्रयासों के बनुसार या तो विभागीय निर्माण संगठन को निर्माण कार्य सौंप दिया जाता है या निजी ठेकदारों से या सरकारी क्षेत्र के निर्माण निगमों से इनका निर्माण कराया जाता है ।

## Development and completion of Rajasthan Canal

1547. SHRI SATISH AGARWAL: Will the Minister of ENERGY AND IRRIGATION AND COAL be pleased to state:

(a) whether it is a fact that world Food Programme has evinced interest and assured cooperation for the development and completion of the Rajasthan Canal Area and the Canal system;

(b) if so, the nature of ass stance that has been offered by WFP in this connection;

(c) what would be the total contribution of the WFP for the development of the canal system and for the adjoining areas separately and how many additional worker can be engaged under this scheme; and

(d) whether the offer has been accepted, if so, its terms and conditions and by what time it will be implemented ?.

THE MINISTER OF ENERGY AND IRRIGATION AND COAL (SHRI A B A GHANI KHAN CHAU-DHURI):(a) The World Food Programme (WFP) has been providing food aid for the labourers working on the Rajasthan Canal Project since September, 1968.

(b) The WFP has offered commodities such as wheat, edible oil, dried skim milk, pulses and be ns. These commodities are sold to the labourers at conces sional prices.

(c) The total contribution of WFP for the R jasthan Canal Project would be about 21 million dollars (Rs. 16 8 crores) and is estimated to generate employment of about 98 mill on man days.

(d) The offer has been accepted by the Government of India. According to the terms and conditions, the WFP supplies commodities and these are sold at about half the prevailing market prices to the labourers working on the Rajasthan Canal. The amount realised from the sale of commodities supplied by WFP is utilised for the development schemes relating to Agriculture, Soil Conservation Animal Husbandry, Forest Nurseries and Plantations. Besides, during the current phase of deve-lopment, the amount will be utilised for the provision of medical and health facilities, safe drinking water supply, schools, provision of veterinary facili-ties for the development of animal husband y etc. According to the present airangement, the WFP assistance be continued till 1983. is to

## कांयला उद्योग के राष्ट्रीयक रण के पक्ष्यातः कांयले के मुल्प और उपलब्धता

1548. श्री हरि कृष्ण शास्त्री : क्या उर्जा, सिंचाई और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करोगे कि क्या कोयला उद्योग के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् कोयले के मूल्य और उसकी उपलब्धता की स्थिति असंतोषजनक रही ही ?

उज्जा, सिंचाई और कोयला मंत्री (भी ए.बी.ए. गनी खान चांधरो): राष्ट्रीयकरण के बाद कोयले का उत्पादन 1973-74 के 78 मिलियन टन से बढ़कर 1976-77 में 101 मिलियन टन हो गया और इसके बाद वह बढ़कर 1978-79 में 102 मिलियन टन हुआ । खान महाना स्टाक भी अप्रैल, 1974 के 6.43 मिलियन टन के मुकाबले अप्रैल, 1979 में बढ़कर 14.34 मिलियन टन हो गया । कायले की मांग 1976-77 तक कुल मिलाकर पूरी ही की जाती रही । कुल विशेष किस्म के कोयले के उत्पादन में कमी और रोल परिवहन की उपलब्धि में कमी के कारण 1977-78 और 1978-79 में उप-भोक्ताओं को कोयला कम मिला ।

जो खान मुहाना कीमत 1-4-1975 में नियत की गई थी वह 17-7-1979 तक वही बनी रही । इस तारीख को इसमें संशो-धन किया गया था । इसमें संशोधन वावश्यक हो जाने के कारण थे-- मजदूरी में बृद्धि बौर उत्पादन के साधनों आगदि की लागत बढ़ जाना ।